इलाहाबाद में टेलीफोन सेवाओं का जीर्णोद्धार

1542. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन सेवाओं के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांच अंकों वाले टेलीफोन से चार अंकों वाले टेलीफोन नहीं लग पाते, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 2700 लाइनों के स्ट्रोजर एक्सचेंज को 1989 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदला जा रहा है। इसके अलावा, मिशनवेहतर संचार के अन्तर्गत इलाहबाद जिले की टेलीफोन सेवाओं का जीर्णोद्धार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) आंतरिक और बाह्य संयंत्रों, विशेषकर अन्तर एक्सचेंज कार्यकरण में सुधार के लिए अन्तर एक्सचेंज जंक्शनों का सघन परीक्षण।

(2) पुराने उपस्कर को बदलना।

(3) पुराने उपभोक्ता उपस्करों को सुधरे टेलीफोन उपकरणों से बदलना।

(4) वितरण प्वाइंटों (डी पी) की पुनःस्थापना।

(5) उपभोक्ता लूपों को इन्स्युलेटेड वायरों द्वारा बदलना।

(ख) जी, हां। पहले चार अंकों वाले स्ट्रोजर तथा 5 अंकों वाले क्रासबार एक्सचेंजों के अन्तर एक्सचेंज कार्यकरण में कुछ तकनीकी समस्या थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं तथा पर्याप्त सुधार हुआ है। इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को चालू करने के पश्चात् सेवा मे और सुधार होगा।

Setting up of Petrochemical Complexes by M|s. Reliance Petrochemicals Limited

1543. DR. RATNAKAR PANDEY: SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether some licences for setting up of Petrochemical complexes with foreign collaboration have been issued By Government to M/s. Reliance Petrochemical Ltd.; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) M/s. Reliance Petrochemicals Limited has not been issued any licence for setting up of Petrochemical Complex.

(b) Does not arise.

Beneficiaries of DPCO, 1987

1544. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any survey has been conducted to and out the real beneficiaries of the DPCO, 1987;

(b) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor;

(c) whether Government have received representations from associations of Industry/consumers that the biggest beneficiary of the DPCO, 1987 is the trade; and

(d) what steps Government propose to take to reduce the margin of